प्रश्न सं. [क्र. 4420] **प्रपत्र-अ**

सदन में उत्तर दिनांक 16.03.2021

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4420 द्वारा माननीय विधायक श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.)

इंटरप्राईजेस रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम न बनने एवं अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण निम्नानुसार है :-

वर्ष 2012 में म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा मेसर्स व्यामटेक को संपूर्ण एमआईएस, जिसमें ईआरपी सिस्टम भी एक घटक था, के क्रियान्वयन हेतु अनुबंधित किया गया था, जिसकी अनुबंध राशि 37.93 करोड रूपये थी। उक्त अनुबंध को फर्म द्वारा नियत समय सीमा में पूर्ण ना किये जाने के कारण 13 अगस्त, 2014 को निरस्त करना पड़ा। तत्पश्चात फर्म पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार राशि रूपये 3.80 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई तथा दंडस्वरूप फर्म को तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया था। अत: परियोजना का क्रियान्वयन अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य ना कर पाने के कारण प्रभावित हुआ। फर्म द्वारा न्यायालयीन विवाद तथा मध्यस्था (आर्बिट्रेशन) की शर्तों के तहत विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की गयी परन्तु अंतत: म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा अनुबंध को निरस्त करने के निर्णय को न्यायालय एवं मध्यस्था में सही पाया गया।

वर्ष 2015 में परियोजना के पुन: क्रियान्वयन हेतु नए सलाहकार मेसर्स डेलोइट को नियुक्त किया। तत्पश्चात मेसर्स डेलोइट द्वारा परियोजना का पुनर्मूल्यांकन तत्समय उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए किया गया। जिसके फलस्वरूप इस परियोजना में ईआरपी समाधान (ERP Solution) के साथ निम्नानुसार घटकों को भी शामिल किया गया :-

- डाटासेन्टर
- ई-मेल समाधान
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग समाधान
- डब्ल्यूएएन (WAN) कनेक्टिविटी
- स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) समाधान
- जनरेशन कंट्रोल सेंटर समाधान (GCC Solution)

इस परियोजना को 'ई-जेनको' नाम दिया गया एवं कुछ अन्य घटकों को भी शामिल किया गया। म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा जून, 2016 में सम्पूर्ण परियोजना की पुनरीक्षित लागत 116 करोड़ रूपये को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

निरन्तर.....

प्रारंभ में ईआरपी के क्रियान्वयन हेतु ओ.ई.एम. आधारित निविदा अप्रैल, 2017 में जारी की गयी थी परन्तु किसी भी ओ.ई.एम. की प्रतिक्रिया न होने के कारण इसे निरस्त कर पुन: सिस्टम इंटीग्रेटर आधारित निविदा आमंत्रित की गयी, जिसमें दो निविदाएं प्राप्त हुई परन्तु उद्धत दर, आंकलित मूल्य से काफी अधिक होन के कारण मार्च, 2019 में इस निविदा को कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा निरस्त कर परियोजना लागत पुन: निर्धारित कर पुन: निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस परियोजना के तहत जनरेशन कंट्रोल सेंटर समाधान (GCC Solution) एवं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) समाधान के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त रूप से खुली निविदा आमंत्रित कर एक कार्यादेश मेसर्स स्टीग एवं टेलीएक्सेल को वर्ष 2018 में जारी किया गया। पार्टनर फर्म टेलीएक्सेल द्वारा जाली बैंक गारंटी जमा करने के कारण इस कार्यादेश को निरस्त करना पड़ा तथा मेसर्स टेलीएक्सेल को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया और दंडस्वरूप 50 लाख की प्रतिभूति राशि को राजसात किया गया।

तदुपरांत सलाहकार के माध्यम से लागत का पुननिर्धारण कर परियोजना प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के उपरांत प्रतिवेदन की समीक्षा, संचालक मण्डल के पूर्व निर्देशानुसार, म.प्र. शासन के उपक्रम मैप-आईटी द्वारा की गयी। मैप-आईटी से प्राप्त अनुशंसा को परियोजना प्रतिवेदन में समायोजित करने के बाद दिसम्बर, 2019 में संचालक मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ईआरपी के लिए जून, 2020 में निविदा आमंत्रित की गयी, जिसमें 3 निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा जमा की गयी। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 27 जनवरी, 2021 को खोला गया। वर्तमान में उपरोक्त निविदाओं का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

इस प्रोजेक्ट में ईआरपी समाधान (ERP Solution) के साथ अन्य घटक भी शामिल है, ईआरपी समाधान के साथ समस्त घटकों को मिलाकर वर्तमान अनुमानित लागत 203 करोड़ रूपये है।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल